

लॉरेंस गैंग से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने किया किनारा

● **सलमान के घर फायरिंग,बाबा सिद्दीकी-मूसेवाला की हत्या जैसी वारदातें साथ कर चुके**

जालंधर (एजेंसी)। देश और विदेश में अपना नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस का गैंग दो फाड़ हो गया है। कनाडा से लॉरेंस का गैंग संभाल रहा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब रोहित गोदारा को साथ लेकर अलग हो गया है। इन गैंगस्टरों ने साथ मिलकर सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी का मर्डर जैसी चर्चित वारदातों को अंजाम दिया था। लॉरेंस गैंग और पंजाब पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिस्नई हैं।

चिराग पासवान के ऐक्टिव होने से बिहार बीजेपी सतर्क

● **‘किंग मेकर’ गेम प्लान के खुलासे के बाद एनडीए में हलचल**

पटना (एजेंसी)। हाल के हफ्तों में, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से बिहार लौटने और विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई, जिसे राज्य की राजनीति में किंगमेकर या किंग नहीं तो किंग की भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है। और यह संदेश भाजपा नेतृत्व के लिए भी सही है। जबकि भाजपा नेतृत्व



का कहना है कि पासवान अपनी पार्टी को सीट बंटवारे के तहत आवंटित किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं , सत्तारूढ़ पार्टी के एक वर्ग का कहना है कि वह केवल राज्य इकाई में भ्रम की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पासवान ने हाल ही में कहा कि वह बिहार की राजनीति में वापस आने के लिए तैयार हैं क्योंकि राज्य के विकास में योगदान देना हमेशा से उनकी प्रेरणा रही है।

मैतेई लीडर की गिरफ्तारी से फिर सुलगा मणिपुर

● **प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डाला** ● **कई गाड़ियां फूकीं,पत्थर से भी हमला,5 जिलों में इंटरनेट बंद**

इंफाल (एजेंसी)। 3 मई 2023 को कुकी-मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। इन दो सालों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6 हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। मणिपुर में मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता करन सिंह को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2023

में हिंसा भड़काने के आरोप है। इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद शनिवार देर रात मणिपुर में हिंसा



भड़क गई थी। राजधानी इंफाल के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी, सड़कों पर टायर और पुराने फर्नीचर भी जलाए।

प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। सरकार ने 7 जून की रात 11:45



बजे से पांच दिनों के लिए 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी है। इनमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थोबल,

काकचिंग और बिष्णुपुर शामिल हैं। इंफाल ईस्ट और बिष्णुपुर में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मणिपुर में 3 मई

2023 को कुकी-मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6 हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की।

राफेल जेट को अब मिलेगा ‘मेक इन इंडिया’ का टच



नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप ने मिलकर हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमानों का फ्यूजलेज बनाने का फैसला किया है। फ्यूजलेज विमान का मुख्य ढांचा होता है। यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुए 63,887 करोड़ रुपये के बड़े समझौते का हिस्सा है। इस समझौते में भारत की नौसेना के लिए 26 राफेल-मरीन जेट विमान खरीदे जाएंगे। इन विमानों की डिलीवरी 2028 से 2030 के बीच होने की उम्मीद है। यह पहली बार है कि डसॉल्ट कंपनी फ्रांस के बाहर राफेल विमान के फ्यूजलेज का उत्पादन करेगी। हैदराबाद में बनने वाली यह यूनिट बहुत महत्वपूर्ण होगी।

ग्लोबल एयरोस्पेस हब बनने के लिए है तैयार है भारत!

इससे पता चलता है कि भारत की एयरोस्पेस निर्माण क्षमता पर भरोसा बढ़ रहा है। इस नई यूनिट में मल्टी-रोल फाइटर जेट के कई महत्वपूर्ण हिस्से बनेंगे। इनमें लेटरल रियर शेल, फुल रियर सेक्शन, सेंट्रल फ्यूजलेज और फ्रंट सेक्शन शामिल हैं। भारतीय वायु सेना पहले से ही राफेल विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इस कदम से भारत की भूमिका इसकी ग्लोबल स्प्लाइं चैन में और भी मजबूत होगी। हैदराबाद में यह दूसरा बड़ा एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग साइट होगा। इससे पहले टाटा-बोइंग का जॉइंट वेंचर भी यहां अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के फ्यूजलेज बनाता है। इन हेलीकॉप्टरों को भारत ने अमेरिका से खरीदा है। डसॉल्ट-टाटा की यह साझेदारी ऐसे समय में हो रही है जब भारत सरकार अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम (एडवांस्ड मीडियम कॉन्वैट एयरक्राफ्ट) को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल रही

है। इसमें सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल होगी। विदेशी कंपनियों के साथ बढ़ते सहयोग, घरेलू इनोवेशन और सरकारी मदद से



अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है। डसॉल्ट और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच सहयोग से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात को कम किया जाए। इसे ही ‘आत्मनिर्भरता’ कहा जा रहा है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च

असम से बाहर निकाले जाएंगे अवैध बांग्लादेशी

● **सरमा बोले-अब 1950 में बने कानून का होगा इस्तेमाल**

दिसपुर (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब अवैध प्रवासियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के निष्कासन के लिए विदेशी न्यायाधिकरणों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, सरकार अब सीधे 1950 के कानून का उपयोग करेगी, जो अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा,सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6 पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। असम में प्रवासियों को सीधे निष्कासित करने के लिए पहले से ही एक वैध कानून मौजूद है।



इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। लेकिन 2020 से 2024 के बीच उसके सैन्य आयात में 9.3 फीसदी की कमी आई है। इसकी तुलना 2015-2019 के पिछले पांच वर्षों से की गई है। फ्यूजलेज किसी भी लड़ाकू विमान का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका स्थानीय स्तर पर निर्माण होना इस बात का संकेत है कि भारत एयरोस्पेस उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद की यह फैसिलिटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4.5-जनरेशन का राफेल विमान भारत के 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट में सबसे आगे है। इस प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती अनुमानित लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये है। भारतीय वायु सेना में फाइटर जेट की कमी को पूरा करने के लिए इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। डसॉल्ट और टाटा ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि पहले फ्यूजलेज सेक्शन वित्त वर्ष 2028 में बनने शुरू हो जाएंगे। इस फैसिलिटी से हर महीने दो पूरे फ्यूजलेज बनाने की उम्मीद है। यह फैसिलिटी एक हाई-प्रिंसिजन एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में काम करेगी। यह न केवल भारत की रक्षा तैयारियों में योगदान देगा, बल्कि ग्लोबल मदद करेगा।

जस्टिस यशवंत वर्मा उठा सकते हैं बड़ा कदम

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाने के लिए राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू कर दी है। अब जस्टिस वर्मा के सामने महाभियोग से बचने का केवल एक ही विकल्प है। अगर वह प्रस्ताव आने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो महाभियोग से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हटाने के मामलों के जानकारीदार लोगों का कहना है कि संसद में खुद का बचाव करने से बचने के लिए वह मौखिक रूप से ही इस्तीफा का ऐलान कर सकते हैं। अगर वह खुद से ही इस्तीफा दे देते हैं तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की तरह ही उन्हें पेंशन और बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हालांकि अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना पड़ता है तो उन्हें पेंशन तक नहीं मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति को

● **महाभियोग से बचने का अब बचा है एक ही रास्ता**

● **मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार भी हुई ऐक्टिव**

पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें किसी की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती है। इस्तीफा देने के लिए जज का पत्र ही काफी होता है। अगर जज अपने पत्र में इस्तीफा देने की कोई तारीख बताता है तो उसतारीख से पहले उसके पास इस्तीफा वापस लेने का भी अधिकार होता है।



और विश्वसनीयता नौकरी के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टेबल जागेश्वर सिंह एक अनुशासित अर्धसैनिक बल का सदस्य था, जो एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र में तैनात था। उसे कैश बाँक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, उसने अपने विश्वास और भरोसे को दरकिनार कर कैश बाँक्स को तोड़ दिया। कॉन्स्टेबल जागेश्वर सिंह को 30 नवंबर, 1990 को आईटीबीपी में भर्ती किया गया था और वह 4-5 जुलाई, 2005 की मध्यरात्रि को कोटे में संतरी के रूप में ड्यूटी कर रहा था, जहां जवानों को सैलरी के रूप में दिए जाने

वाले लाखों रूपए से भरे कैश बाँक्स रखे हुए थे। सिंह ने कथित तौर पर ताला तोड़ दिया और नकदी ले ली, इसके बाद कैश बाँक्स को कोटे से लगभग 200 गज की दूरी पर छिपा दिया और पोस्ट से भाग गया। जब घटना कंपनी कमांडर को पता चली तो उन्होंने तुरंत आस-पास के इलाके के साथ-साथ उत्तरकाशी की ओर जाने वाले वाहन की भी तलाशी ली, लेकिन आरोपी भाग निकला। कंपनी कमांडर ने तब मामले की सूचना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को दी और बाद में 6 जुलाई, 2005 को कॉन्स्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हुई, जिसमें जवान दोषी पाया गया।

ताउम्र यही गलती करते रहे,धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे

राहुल को फडणवीस का जवाब,‘मैच फिक्सिंग’ के आरोप पर घेरा

मुंबई (एजेंसी)। राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ‘मैच फिक्सिंग’ के आरोप पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब आया है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहाकि ताउम्र आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे।



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहाकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में हार पर आत्मवलोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। फडणवीस ने समाचार पत्र में प्रकाशित अपने लेखों में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बिहार सहित आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें मिलने वाली हार के लिए बहाने तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने

शनिवार को कई अखबारों में प्रकाशित एक लेख और एक्स पर पोस्ट साझा कर आरोप लगाया था। इसमें उन्होंने कहाकि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था और यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा कर गांधी ने चुनाव में कथित अनियमितताओं के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया कि कैसे मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया। मतदान प्रतिशत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया। फर्जी मतदान कराया गया और बाद में सबूतों को छिपा दिया गया। निर्वाचन आयोग ने आरोप को खारिज करते हुए कहाकि अनुकूल परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। गांधी के दावों के जवाब में फडणवीस ने सब कुछ बताया है।

हनीमून कपल के साथ शिलांग में क्या हुआ, गाइड के बयान से नया संदेह

इंदौर। हनीमून मनाने गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला उलझता ही जा रहा है। राजा का 2 जून को शव मिला, लेकिन, अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं है। इस मामले में संस्पेंस बढ़ता जा रहा है। मामले में एक नया मोड़ ले लिया। राजा और सोनम मामले में एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पंडे के ताजा बयान से संस्पेंस और बढ़ गया है। उन्होंने राजा और सोनम के साथ तीन लोगों को देखा था। स्थानीय गाइड के मुताबिक, 23 मई की सुबह करीब 10 बजे उसने राजा-सोनम को 3 अन्य पुरुष पर्यटकों के साथ देखा था। राजा आगे तीनों के साथ चल रहे थे, सोनम पीछे थी। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम से 11 मई को इंदौर में धूमधाम से हुई थी। अपने हनीमून के लिए दोनों 20 मई को बेंगलुरु के रास्ते गुवाहाटी पहुंचे और कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद 23 मई को शिलांग चले गए। वहां से वे चैरापूंजी के पास नौग्रीट गांव में प्रसिद्ध ‘लिविंग रूट ब्रिज’ देखने गए। 23 मई को सोनम ने अपनी सास से आंखिरी बार बात की, जिसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए।

सीबीआई जांच के लिए आग्रह

सीएम डॉ. मोहन यादव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि संकट की इस घड़ी में मध्यप्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मप्र के पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क कर रहे हैं। सीबीआई जांच आदेशित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है।

पिता ने ज्योतिष की सलाह पर घर के बाहर सोनम का उल्टा फोटो टांगा



पिता को अशुभ मुहूर्त की आशंका

सोनम रघुवंशी के पिता ने बेटी की उल्टी तस्वीर रखावे पर लटकाई है। उन्हें उम्मीद है कि कोई चमत्कार सोनम को बचाकर ले जाएगा। क्योंकि, दोनों बिना शुभ मुहूर्त के ही घूमने गए थे। पति राजा रघु वंशी के साथ हनीमून मनाने गई और शिलांग में लौपता हुई इंदौर की सोम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने बेटी की सलामती के लिए अब आध्यात्मिक उपायों का सहारा लिया है। देवी सिंह ने घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर लटकाई गई। उनका कहना है कि ज्योतिषी से सलाह लेकर यह कदम उठाया गया है। उन्हें उम्मीद है कि इस उपाय से उनकी बेटी सुरक्षित घर लौट आएगी। घटना के बाद पहली बार केमरे के सामने आए देवी सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा तो चला गया, अब बेटी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। पूरे परिवार की उम्मीदें अब भगवान और बेटी की किस्मत पर टिकी हैं।

सर्चिंग शुरू, संदेहियों की जांच

भाई विपिन ने बताया कि लापता बहु सोनम के भाई गोविंद ट्रिस्ट प्लेस पर है। जिस स्थान पर सर्चिंग चल रही है वहां के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। गोविंद ने बताया कि पचास फीट खाई में अब तक पुलिस सोनम को तलाशती रही। जिस स्थान पर सोनम का रेनकोट मिला उसे पिन पाइंट बनाते हुए सर्चिंग टीम अब रोड पर तलाश कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो सोहरा के होटल का है। यहां राजा और सोनम ने अपने बैग रखे थे। केमरे में दिख रहा है कि जिस स्थान पर दोनों खड़े हैं वहां लाल रंग की कार के पास दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं, जिनमें से एक के चेहरे पर मास्क है। दोनों फोन पर बात कर रहे रहे हैं। पुलिस इस ओर भी जांच करने की बात कह रही है।

बिना किसी को बताए घूमने निकले

देवी सिंह ने बताया कि बेटी और दामाद बिना किसी को बताए 21 मई को घूमने निकल गए थे। जबकि उन्होंने ज्योतिष से सलाह लेकर बेटी की विदाई के लिए 5 जून का शुभ मुहूर्त निकलवाया था। बच्चों ने बिना बताए यात्रा की योजना बना ली। 21 मई की सुबह पता चला कि दामाद राजा सोनम को लेकर जा रहे हैं। कहा गया कि वे कामाख्या देवी के दर्शन को जा रहे हैं, फिर शिलांग पहुंचे। सोनम के पिता कह रहे हैं कि पुलिस होटल वालों को बचा रही है। जो भी राज निकलेंगे, वो होटल से ही निकलेंगे। पिता का कहना है कि सोनम और राजा के भाइयों से होटल वाले दो दिन तक कहते रहे कि सारा सामान कमरे में रखा है, जिस कमरे में जिसमें राजा और सोनम ठहरे हुए थे। फिर पुलिस ने कहा कि उनको सामान रात 11 बजे नाले के पास से मिला। अब पहला सवाल ये उठता है कि जो सामान कमरे में दो दिन तक रखा, वो नाले के पास तीसरे दिन कैसे मिला? उसको कमरे से बाहर निकालकर नाले के पास कौन ले गया? दूसरा सवाल यह कि जो पुलिस वाले शाम 6 बजे ही जांच बंद करके जंगल में जाने से मना करते रहे। वो रात 11 बजे नाले के पास क्या करने पहुंचे थे, जहां उनको सामान मिला।

जेवर, नकदी साथ ले गई सोनम- पिता ने बताया कि सोनम के पास जेवर और नगद राशि थी। मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी जैसे गहनों के साथ वह यात्रा पर निकली थी। उनका मानना है कि किसी की नीयत खराब हो गई होगी।

सड़क दुर्घटना के प्रभावितों के लिए ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025’ लागू

कलेक्टर ने अस्पताल संचालकों को 3 दिन में पंजीयन कराने को कहा

इंदौर। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित और नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025’ लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल किसी भी व्यक्ति का इलाज इंदौर के अस्पतालों में नकदी रहित (कैशलेस) रूप से किया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपए तक होगी। इस क्रम में कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को जिले के अस्पताल संचालकों की बैठक लेकर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अस्पताल तीन दिन में अपना पंजीयन करा लेंगे।

कलेक्टर ने अस्पताल संचालकों से आग्रह किया कि वे स्कीम के तहत चिह्नित प्रक्रिया का पालन करें तथा शिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। सभी संबंधित विभागों, अस्पतालों एवं संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’ का पालन सुनिश्चित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र और समुचित उपचार उपलब्ध हो सके। उन्होंने

कहा कि घायलों का समय पर इलाज और मदद देना राज्य शासन की प्राथमिकता है। केंद्र शासन की उपरोक्त योजना के अलावा राज्य शासन ने राहगीर योजना भी लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल अपने पूर्ण स्वरूप में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि सभी अस्पताल आगामी तीन दिन में अपना पंजीयन करवा ले जिससे कि अगले सात दिन में यह योजना अपने पूर्ण स्वरूप में लागू की जा सकेगी। बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति मोटरयान दुर्घटना में घायल होता है, तो उसे अधिकतम सात दिनों तक चुनिंदा अस्पताल में नकदी रहित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना के उपरांत किसी अन्य अस्पताल में केवल स्थिरीकरण प्रक्रिया के लिए ही उपचार की अनुमति होगी, इसके बाद मरीज को उपचार के लिए निर्दिष्ट अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा। योजना अंतर्गत प्रति पीड़ित को अधिकतम डेढ़ लाख तक का नकदी रहित उपचार प्रदान किया जाएगा। योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-215 (3) के अंतर्गत गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी।

इंदौर में मेट्रो की फ्री सवारी खत्म, तीन महीने सस्ते किराए का सुख

इंदौर। रविवार से मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना शुरू हो गया। एक हफ्ते तक चला फ्री और जॉय राइड वीक अब खत्म हो गया। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब इसका ध्यान रखना होगा। अब दो स्टेशनों के बीच सफर करने पर 5 रुपए और पांच स्टेशनों तक यात्रा करने पर 8 रुपए का टिकट लगेगा। हालांकि, 8 से 15 जून तक मेट्रो किराए में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेशन (गांधी नगर) से मेट्रो में चढ़कर पांचवें स्टेशन वीरांगना झलकारी बाई (टीसीएस) स्टेशन पर उतरने पर यात्री को 8 रुपए किराया देना होगा। यदि यात्री वीरांगना झलकारी बाई स्टेशन से वापस देवी अहिल्याबाई

होलकर स्टेशन तक यात्रा करता है, तो उसे फिर से 8 रुपए का टिकट लेना होगा। पिछले एक हफ्ते में 1.50 लाख से अधिक लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। अब बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना भी लगेगा। मेट्रो के शुभारंभ के दिन 25 हजार से अधिक यात्रियों ने सफर किया था, जबकि 1 से 7 जून तक टिकट लेकर कुल 1 लाख 43 हजार 301 यात्रियों ने यात्रा की। इंदौर में अभी सिर्फ 5.9 किमी पर ही मेट्रो चलेगी। जबकि पूरा प्रोजेक्ट 31 किमी लंबा है। मिड सेवशन अंडरग्राउंड है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी यहां काम शुरू नहीं हुआ है।

भस्म आरती दर्शन

पंचामृत पूजन के बाद रजत की मुण्डमाल, रुद्राक्ष की माला और आभूषणों से भगवान महाकाल का श्रृंगार

उज्जैन (एजेंसी)। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार तड़के भस्म आरती के दौरान चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत पूजन किया। प्रथम घंटा ल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद भगवान के मस्तक पर भांग चन्दन और त्रिगुण्ड अर्पित कर श्रृंगार किया गया। श्रृंगार पूरा होने के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढांककर भस्मी रमाई गई। भगवान महाकाल का भांग

झ्रायफूट चन्दन आभूषण और फूलों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भस्म अर्पित करने के पश्चात शेषनाग का रजत मुकुट रजत की मुण्डमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ-साथ सुगन्धित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की। भगवान महाकाल ने मोरारे और गुलाब के सुगंधित पुष्प धारण किए। फल और मिष्ठान का भोग लगाया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महा निर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गयी। मान्यता है की भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते है।

इंदौर में तलाकशुदा महिला से रेप इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर धोखा, केस दर्ज; आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के बाणगंगा में रहने वाली एक 18 साल की महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके परिचित के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता तलाकशुदा है। आरोपी से उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। बाणगंगा पुलिस ने महिला की शिकायत पर रवि पुत्र हीरालाल यादव निवास ग्राम जाख्या के खिलाफ रेप और शादी के नाम पर धोखा देने के मामले में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि वह तलाकशुदा है। 2024 में रवि से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। फिर कुछ दिनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत होती रही। इस दौरान रवि ने एक दिन पीड़िता को कहा कि वह उसे पसंद करता है उसका शादी का मन है। पीड़िता ने अपने बारे में बताया। तब रवि किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कही। 12 जनवरी को घूमने के बहाने होटल में जबरदस्ती संबंध बनाए- पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 12 जनवरी को रवि ने सुबह पीड़िता को घूमने के बहाने अपने साथ ले गया और एक होटल में जबरदस्ती संबंध बनाए। बाद में विवाह की बात टाल दी।

फोटोग्राफर ने की आत्महत्या, एक साल पहले हुई थी शादी

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में देर रात एक फोटोग्राफर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान संदीप सोनिया के रूप में हुई है, जो स्कीम नंबर 78 में अपने परिवार के साथ रहता था। घटना के समय वह अपने पिता के साथ घर पर अकेला था। करीब एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। पुलिस के अनुसार, संदीप (24) ने अपने घर की ऊपरी मंजिल पर फांसी लगाई। देर रात जब उसके पिता मनोहर ऊपर कमरे में पहुंचे, तो बेटा फंदे पर लटका मिला। तुरंत परिजन उसे एमबाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। संदीप के मोबाइल की जांच की जाएगी।

पिता की बीमारी का बहाना बनाकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराया

पेट्रोल पंप के सेल्समैन और अन्य कर्मचारी के साथ ठगी, एक्टिवा नंबर से पकड़ाए आरोपी

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के कनाड़िया इलाके में दो युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ऑनलाइन पेमेंट का झांसा देकर नकदी ठग ली। आरोपी एक्टिवा पर सवार होकर पहुंचे और अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने की कहानी सुनाकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 6 हजार रुपए ले गए। बाद में पता चला कि खते में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। कनाड़िया पुलिस के अनुसार, मित्रबंधु नगर निवासी नितिन पाटीदार की शिकायत पर एक्टिवा पर सवार दो युवक धीरज और सुयश के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, 22 मई को नितिन कनाड़िया स्थित पाटीदार प्यूल् स्टेशन पर ड्यूटी पर था। रात के समय एक्टिवा से दो युवक पहुंचे और पिता की तबीयत गंभीर होने



की बात कहकर 6 हजार रुपए नकद की जखूरत बताई।

ट्रांजेक्शन स्क्रीन दिखाकर किया विश्वास- युवकों ने कहा कि उनके पिता फोनिकस अस्पताल में भर्ती हैं और दवाइयों के लिए तत्काल रुपए चाहिए। उन्होंने फोन-पे से भुगतान करने की बात कही और ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट दिखाकर पैसे ले लिए। लेकिन पंप के अकाउंट में राशि नहीं पहुंची। दो दिन बाद तक पेमेंट नहीं आने पर नितिन ने अपने मैनेजर को जानकारी दी।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में भी फर्जीवाड़ा: देश में 123 फर्जी वेबसाइटों से ठगी

जनता से सतर्क रहने की अपील, सही वेबसाइट से ही पंजीयन करें

इंदौर। मार्कशोट, डिग्री और जाति प्रमाण पत्र के बाद अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों में भी फर्जीवाड़े के मामले सामने आने लगे। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, देशभर में केवल एक अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही जन्म और मृत्यु का पंजीयन वैध माना गया है। लेकिन, अब तक 123 फर्जी वेबसाइटें लोगों को गुमराह कर रही हैं और प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं, जो जांच में फर्जी पाए जाते हैं। दौषपूर्ण प्रमाण पत्र जारी होने पर न केवल व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, बल्कि उसकी कानूनी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश ने केंद्र से मिले निर्देशों के आधार पर जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। जिला सांख्यिकी अधिकारी माधव बेंडे ने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के अनुसार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि केवल सरकारी अधिकृत वेबसाइट से ही पंजीयन करें। शहरी क्षेत्र में यह कार्य नगर निगम/परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम बताना होता है। सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है। केंद्र और राज्य में स्थित चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल के पास इसका रजिस्ट्रेशन होता है। गांवों और कस्बों में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास इस काम को अंजाम दिया जाता है।

बढ़ी गर्मी, तापमान 37 डिग्री से ज्यादा, एक हफ्ते तक उमस का रहेगा दौर

मानसून की एंट्री 15 जून के बाद



इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में पिछले चार दिनों से दिन के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को सुबह बादल छाए रहे, लेकिन दिनभर तेज धूप खिली रही। इस दौरान तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। रात का तापमान भी पिछले तीन दिनों से 23 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। इधर, रविवार सुबह से ही मौसम साफ था और गर्मी का अहसास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने

वाले एक सप्ताह तक गर्मी और उमस बनी रहेगी। इंदौर में मानसून की एंट्री 15 जून के बाद ही होने की संभावना है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। शक्रवार को यह तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। फिलहाल दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री और रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। इसी कारण पिछले तीन दिनों से तेज धूप और उमस का माहौल है।

नौतपा के समय जो गर्मी नहीं पड़ी, उसकी भरपाई अब जून में हो रही है।

12 जून तक सक्रिय होगा नया सिस्टम- अगले सात दिनों तक सुबह से दोपहर तक तेज धूप रहने की संभावना है। हालांकि राहत इस बात की रहेगी कि दोपहर के समय धूप चरम पर पहुंचने के साथ ही बादल छाने और हवा चलने लगेगी। शहर के कुछ क्षेत्रों में लोकल वेदर सिस्टम के कारण कुछ मिमंटों की हल्की बारिश भी हो सकती है।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



अभी कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की, जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई। उप-राष्ट्रपति, सांसदों एवं राजनेताओं ने इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। एक दुर्लभ कदम के तहत, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा इस पर सर्वोच्च न्यायालय से इस पर राय मांगी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यापालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है? संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय को अब संदर्भ का उत्तर देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया था कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए उसके द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में मान ली गई सहमति होगी। संदर्भ में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मान ली गई सहमति की अवधारणा संवैधानिक योजना से अलग है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को मौलिक रूप से सीमित करती है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए 14 तीखे सवाल भेजे। इसमें इस बात पर जोर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201, जो राज्यापालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, कोई समय-सीमा या विशिष्ट प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ निर्धारित नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए उनमें पहला सवाल यह है कि जब राज्यपाल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या हैं? दुसरा प्रश्न जब राज्यपाल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या वह अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? चौथा प्रश्न, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? पांचवा प्रश्न संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के

सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति के तीखे सवाल और समाधान

संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय को अब संदर्भ का उत्तर देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से इस पर राय मांगी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यापालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है?

अभाव में, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? अन्य प्रश्नों में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय-सीमाएँ लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में, क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति या अन्यथा के लिए विधेयक को आरक्षित करने पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है?

इसके अलावा यह भी राय मांगी गई है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं ? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक को सामग्री पर, किसी भी तरह से, कानून बनने से पहले न्यायिक निर्णय लेना अनुमेय है? साथ ही क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग तथा राष्ट्रपतिभ्राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ? इसके अलावा यह भी शामिल है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू कानून है?

राष्ट्रपति द्वारा यह भी पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे ? यह भी संदर्भित किया गया है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने/आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत हैं? इसके अलावा यह भी राय मांगी गई है कि क्या संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है?

अप्रैल में एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समय सीमा निर्धारित की थी जिसके भीतर राज्यपाल को राज्य विधानसभाओं द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करनी होगी। न्यायालय ने कहा था कि इस समय सीमा का पालन न करने पर



न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि हालांकि अनुच्छेद 200 के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि राज्यपाल को विधेयकों के स्वीकृति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कार्रवाई न करने की अनुमति मिल जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का निर्वहन न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विधेयकों पर निर्णय लेना आवश्यक है और इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण दर्ज करके संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक मामले में पारित फैसले की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई लोगों ने आलोचना की थी। संविधान का अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकें। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की यह राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व काफी अधिक



होता है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत इस तरह की राय कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति ने यह संदर्भ 13 मई को भेजा, जिसमें कुल 14 कानूनी प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों में न केवल विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, बल्कि यह भी पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को खुद यह पहले तय करना चाहिए या नहीं कि कोई मामला संविधान की

व्याख्या से संबंधित है, जिससे उसे बड़ी पीठ को सौंपा जा सके। एक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति की सीमाओं को लेकर भी है। वहीं, अंतिम प्रश्न केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की मूल सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित है कि क्या यह सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है या अन्य अदालतों के पास भी?

इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में राय देने से इंकार किया है। सन् 1993 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में जब मंदिर की पूर्व स्थिति पर राय मांगी गई थी, तब न्यायालय ने धार्मिक और संवैधानिक मूल्यों का हवाला देते हुए मना कर दिया था। सन् 1982 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास से संबंधित एक कानून पर राय मांगी गई थी, लेकिन कानून पारित हो जाने और उस पर याचिकाएं दायर हो जाने से राय अप्रासंगिक हो गई थी। इस बार के मामले को लेकर यह आशंका भी उठी है कि कहीं राष्ट्रपति (सरकार) पहले से दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटना तो नहीं चाहतीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय पहले स्पष्ट कर चुका है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई राय किसी न्यायिक निर्णय की समीक्षा या उसे पलटने का जरिया नहीं बन सकती। सन् 1991 में कावेरी जल विवाद में न्यायालय ने कहा था कि पहले दिए गए निर्णय पर दोबारा राय मांगना न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है।

संपूर्ण विवाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन की बहस को फिर से सामने लाता है। विपक्ष-शासित राज्यों में विधेयकों को राज्यापालों द्वारा लंबे समय तक रोककर रखने या अस्वीकार करने की घटनाओं से यह मुद्दा गरमाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसे 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को केंद्र और राज्य के संबंधों में असंतुलन बताया और समय सीमा जरूरी ठहराई। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को कार्यपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया। अब देखा यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस संवैधानिक मुद्दे पर क्या राय देता है और यह राय केंद्र-राज्य संबंधों और संविधान की व्याख्या को किस दिशा में ले जाएगी।

हिन्दू साम्राज्य दिवस

लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।



छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की स्वतंत्रता के महान नायक हैं, जिन्होंने 'स्वराज्य' के लिए संगठित होना, लड़ना और जीतना सिखाया। मुगलों के लंबे शासन और अत्याचारों के कारण भारत का मूल समाज आत्मदैत्य की स्थिति में चला गया था। विशाल भारत के किसी न किसी भू-भाग पर मुगलों के शोषणकारी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष तो चल रहा था लेकिन उन संघर्षों से बहुत उम्मीद नहीं थी। भारत के वीर सपूत अपने प्राणों की बाजी तो लगा रहे थे लेकिन समाज को जागृत और संगठित करने का काम नहीं कर पा रहे थे। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के भीतर विश्वास जगाया कि हम मुगलों के शासन को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं, यदि सब एकजुट हो जाएं। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देवलोकगमन के बाद भी 'हिन्दवी स्वराज्य' का विचार पल्लवित, पुष्पित और विस्तारित होता रहा। ' हिन्दू साम्राज्य दिवस ' या ' श्रीशिव राज्याभिषेक दिवस ' भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने दुनिया को बताया कि भारत के भाग्य विधाता मुगल नहीं हैं। भारत का हिन्दू समाज ही भारत का भाग्य विधाता है। भारत में हिन्दुओं का राज्य है। उनके शासन का नाम है- ' हिन्दवी स्वराज्य '।

विक्रम संवत् 1731, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को स्वराज्य के प्रणेता एवं महान हिन्दू राजा श्रीशिव छत्रपति के राज्याभिषेक और हिन्दू पद पादशाही की स्थापना से भारतीय इतिहास को नयी दिशा मिली। दासता के घोर अंधकार में स्वराज्य की एक चमकदार रोशनी था- हिन्दवी स्वराज्य। हिन्दू साम्राज्य दिवस को हम भारत के स्वराज्य की हुंकार भी कह सकते हैं, जब हिन्दुओं ने आत्मविश्वास से सीना ठोककर मुगलों को ललकारा और कहा कि भारत में एक बार फिर स्वराज्य की स्थापना हो गई है, जिसमें सबका कल्याण है। अनेक इतिहासकार एवं विद्वान कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना न की होती, तो

भारत के स्वराज्य की हुंकार

भारत का इतिहास कुछ और होता। यह अतिशयोक्तिपूर्ण विचार नहीं है। अपितु भारत के पड़ोसी देशों एवं दूर-दराज के उन देशों की स्थिति को

देशों में वहाँ के मूल समाज की संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जिस प्रकार के अत्याचार मुगल शासक भारत में कर रहे थे, उसके बाद हिन्दू

शासन के अधीन पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। न कोई पूछताछ होती थी, न न्याय मिलता था। अधिकारी जो चाहें, वही करते थे। स्त्रियों के सम्मान का हनन, हत्याएं, हिंदुओं



देखकर सहज कल्पना की जा सकती हैं, जहाँ मूल समाज की अपेक्षा बाहरी आक्रांताओं का शासन स्थायी हो गया। ऐसे

समाज किस स्थिति को प्राप्त होता। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार जीएस सरदेसाई ने लिखा है कि 'मुस्लिम

का जबरन धर्म परिवर्तन, उनके मंदिरों का विध्वंस, गाँवों का वध- ऐसे धिनौने अत्याचार उस शासन में आम बात थे।

रैगिंग

संध्या अग्रवाल



हाल ही में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छात्र के स्वजनों का आरोप है कि रैगिंग के कारण उनके बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ी। इस घटना ने एक बार फिर से रैगिंग के घुरे को उजागर किया है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर छात्र के स्वजनों की बात सच है और सचमुच बच्चे की जान रैगिंग के कारण गई है, तो तत्काल रैगिंग पर रोक लगाने का समय आ गया है। अब किसी और घर का चिराग ना बुझे। अब और कोई बच्चा रैगिंग के चलते अवसाद में ना जाए, इसलिए रैगिंग बंद होना चाहिए। रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो न केवल छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, बल्कि यह उनकी जान भी ले सकती है। रैगिंग के दौरान छात्रों को शारीरिक और

मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वे अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। रैगिंग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को प्रताड़ित करने की मानसिकता। सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, जिससे वे अपनी दबंगई दिखा सकें। लेकिन यह दबंगई कई बार जानलेवा साबित होती है। रैगिंग के प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। रैगिंग के कारण छात्र अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इससे न केवल छात्रों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचता है। रैगिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक

सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए काम करना होगा, जहां छात्र बिना किसी डर के अपनी रैगिंग के प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। रैगिंग के कारण छात्र अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इससे न केवल छात्रों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचता है।

शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें रैगिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे और रैगिंग करने

वालों को सख्त सजा देनी होगी। रैगिंग के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी और छात्रों को इसके खतरों के बारे में बताया होगा। रैगिंग के खिलाफ एकजुट हों और अपने कॉलेजों को सुरक्षित बनाएं। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना होगा, जहां वे बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा कर सकें। रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो न केवल छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, बल्कि यह उनकी जान भी ले सकती है। हमें रैगिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है और अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए काम करना होगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिसमें छात्रों को इसके खतरों और नुकसान के बारे में बताया जा सकता है।

कॉलेजों में छात्र परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां छात्र अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेजों में रैगिंग विरोधी समिति का गठन किया जा सकता है। जो रैगिंग की घटनाओं की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रैगिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने से रैगिंग की घटनाओं में कमी आ सकती है। शिक्षकों और कर्मचारियों को रैगिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाने और छात्रों की समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। छात्रों के लिए समर्थन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, जिसमें वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रयासों से रैगिंग की समस्या का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है और कॉलेजों में एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाया जा सकता है।

झोपड़ी में लगी आग, 2 भैंसों की मौत, 5 झुलसीं

शिवपुरी में बचाते समय 1 युवक का हाथ-पैर जला, मुआवजे की मांग

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी जिले के देवगढ़ गांव में रविवार दोपहर एक खेत की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इस हादसे में दो भैंसों की जलकर मौत हो गई, जबकि पांच भैंसें गंभीर रूप से झुलस गई। आग से भैंसों को बचाने में एक युवक भी झुलस गया है।

खेत पर बनी झोपड़ी में बंधी थीं सात भैंस

देवगढ़ निवासी फूल सिंह लोधी का खेत गांव से एक किलोमीटर दूर है। उन्होंने खेत पर झोपड़ी बनाकर अपनी सात भैंसों को रखा था। रविवार दोपहर करीब 3 बजे फूल सिंह का छोटा बेटा जीतू लोधी खेत पर सो रहा था। तभी अचानक झोपड़ी से आग की लपटें उठती दिखीं। जीतू ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की।

दो भैंसें आग की चपेट में आकर जल गईं

इस दौरान जीतू ने जान की परवाह किए बिना झोपड़ी में बंधी पांच भैंसों को बाहर निकाला, लेकिन सभी झुलस गईं। वहीं दो भैंसें आग की चपेट में आकर जल गईं। आग से भैंसों को निकालने के दौरान जीतू के हाथ और पैर भी झुलस गए।

ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग

फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस घटना में फूल सिंह लोधी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।

रायसेन में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

रायसेन (नप्र)। रायसेन के भोपाल रोड स्थित सदलसपुर में रविवार शाम 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान ग्राम मुंडियाखेड़ निवासी 20 वर्षीय पवन साहू और 26 वर्षीय राजीव विश्वकर्मा के रूप में हुई है। दोनों युवक किसी काम से भोपाल की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वर्तमान में दोनों के शव मॉर्चरी में रखे गए हैं। सोमवार सुबह दोनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मार्ग कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

कगास नदी पर बनेगा 12 फीट ऊंचा पुल बंधवा कोटार-देवरिहनागांव के बीच छह महीने में होगा निर्माण, विधायक ने किया भूमिपूजन

मऊगंज (नप्र)। मऊगंज जिले में कगास नदी पर एक नए पुल का निर्माण होगा। रविवार को शाम 4 बजे बंधवा कोटार और देवरिहनागांव को जोड़ने वाले इस पुल का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर नरेन्द्र प्रजापति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पुल चार स्तंभों पर बनेगा और इसकी ऊंचाई 12 फीट होगी। विधायक प्रजापति ने बताया कि इस पुल से



बारिश के मौसम में ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। पहले अल्प वर्षा में भी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतें होती थीं। निर्माण एंजेंसी को 6 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी बुजेंद्र पांडेय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का 11वां दिन, केंद्रीय कृषि मंत्री बेंगलुरु में किसानों से मिले बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति : शिवराज सिंह चौहान

बेंगलूर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के अंतर्गत किसानों से संवाद किया। 15 दिवसीय इस अभियान की शुरुआत 29 मई को ओडिशा से हुई थी, जो 12 जून तक चलेगा। अब-तक 11 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों जिसमें ओडिशा के साथ-साथ जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश शामिल हैं, का दौरा कर लाखों किसानों से संवाद किया है। इसी कड़ी में आज उन्होंने बेंगलुरु में किसानों से बातचीत की।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में आकर गर्व महसूस हो रहा है। शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रयास सराहनीय हैं। बेंगलुरु ग्रामीण और आस-पास के क्षेत्रों में बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किसानों ने स्वयं भी कई प्रकार के शोध व प्रयोग करके कृषि नवाचार में नए अध्याय जोड़े हैं। आज मैंने ‘कमलम’ (डूंगन फ्रूट) की खेती देखी। ‘कमलम’ की खेती के बारे में किसानों ने अनुभव साझा किए। मुझे जानकारी मिली की ‘कमलम’ की खेती में पहले दो वर्ष तक उतना फायदा नहीं होता, लेकिन तीसरे साल के बाद 6 से 7 लाख रुपये आसानी से बचाए जा सकते हैं। टमाटर के खेतों की भी ध्रमण किया मुझे किसान भाइयों ने ही बताया, कई बार कीमतों में उतार-चढ़ाव के बाद भी 3 से 4 लाख रुपये प्रति एकड़ कमाया जा सकता है।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि ‘लैब से लैंड’ जुड़ना जरूरी है। रिसर्च की रीयल टाइम में किसानों तक पहुंच हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जलवायु और क्षेत्र की विशेषता के अनुसार फलों, सब्जियों और फसलों की उपज की सही जानकारी



किसानों तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना की है। इसलिए विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी हैं। बिना कृषि के विकास संभव नहीं है। आज भी 50 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जीडीपी में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। साथ ही इस वर्ष चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7.5 प्रतिशत है, जिसमें कृषि का योगदान 5.4 प्रतिशत है। कृषि में 1 या 2 प्रतिशत की विकास दर बड़ी मानी जाती है। उस लिहाज में यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार हम कृषि क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसान भाइयों-बहनों को प्रणाम करता हूं, वह चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन आगे भी अर्नत संभावनाएं हैं।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमें चार प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिनमें शामिल हैं-

- 145 करोड़ आबादी के लिए खाद्य

सुरक्षा

- पोषणयुक्त आहार
- किसानों के लिए कृषि क्षेत्र को लाभ में बदलना
- मिट्टी की उर्वरक क्षमता को सुरक्षित रखना

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इन्हीं निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत ‘लैब को लैंड’ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर वहां कि क्षेत्र विशेष की जानकारी के आधार पर, मिट्टी की उर्वरकता की आवश्यकतानुसार, जलवायु व अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किसानों को सही किस्मों व पद्धति के जरिए कृषि में उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दे रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह ने नकली बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रति भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन बीज या कीटनाशक बनाने वालों के प्रति

सरकार सख्ती से पेश आएगी। कानून बनाया जा रहा है। ऐसे कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 16 हजार वैज्ञानिक खेतों में किसानों के पास जाकर शोध की जानकारी दे रहे हैं। ‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ विजन के साथ हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सम्मिलित प्रयासों से भारत को विश्व का ‘फूड बास्केट’ बनने से कोई रोक नहीं संकेगा। हम अपने देश की जरूरतें भी पूरी करेंगे और विदेशों में निर्यात की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की समृद्धि के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसान सीधे अपनी उपज बेच सके, बिचौलियों की भूमिका कम हो इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) बनाई गई है। आलू, प्याज और टमाटर इन तीन फसलों के लिए यदि कोई किसान

कम कीमत के कारण अपने क्षेत्र की जगह बड़े शहरों या ऐसे राज्यों जहां उनकी उपज की कीमत अधिक है, वहां ले जाकर अपनी फसल को बेचना चाहे तो ऐसी स्थिति में परिवहन में होने वाली परिचालन लागत का खर्चा केंद्र सरकार द्वारा उठाना जाएगा। ऐसा तालमेल करने से किसानों की भी उचित दाम मिल जाएगा और जिस क्षेत्र में दाम अधिक है वहां उत्पादन पहुंचने से दाम भी संतुलित हो जाएंगे। अगर भंडारण को लेकर भी सहायता की आवश्यकता होगी तो केंद्र द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना इसी साल निर्मित की गई है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही अन्य कई प्रयास किए जा रहे हैं।

अंत में श्री चौहान ने कहा कि कृषि मंत्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य उपक्रमों से जुड़े प्रत्येक वैज्ञानिक की असली जिम्मेदारी यही है कि किसान भाइयों-बहनों तक शोध की सटीक जानकारी सही समय में पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी किसानों से कहा कि सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर न रहें। आगे बढ़ते हुए कृषि विविधिकरण, प्रोसेसिंग का मार्ग भी चुनें। निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर संभव तरीके से कृषि को किसानों के लिए फायदे में बदलने की कोशिश कर रही है। हर स्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है।

इस अवसर पर सांसद व पूर्व मंत्री एम सी सुधाकर, विधायक, एस आर विश्वनाथ, डॉ. एस के सिंह, महानिदेशक बागवानी संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. राघवेंद्र भट्टा, महानिदेशक, पशु विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, डॉ. वी. सुब्रमण्यम डायरेक्टर बागवानी संस्थान बेंगलुरु, वैज्ञानिक, छात्र, व किसान शामिल रहे।

गांधी मेडिकल कॉलेज में टीएमएस से ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज

ओसीडी से लेकर सिजोफ्रेनिया तक में कारगर, 15 मिनट के सेशन से मिलेगा आराम

भोपाल (नप्र)। ऐसे मानसिक रोगी जिन पर दवाओं असर नहीं होता उनको भी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टीमुलेशन (टीएमएस) मशीन मौजूद है। इस मशीन से गैर-आक्रामक उपचार पद्धति से ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, पैनिक अटैक समेत अन्य ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज सिर्फ 15 से 20 मिनट के सेशन में किया जा रहा है।

मेगनेटिक फील्ड के उपयोग से होता है इलाज- टीएमएस मशीन मस्तिष्क के खास भागों को एक्टिव करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों (मेग्नेटिक फील्ड) का इस्तेमाल करती है। इसमें एक क्राइल होती है। जिसे सिर पर रखा जाता है। यह क्राइल एक छोटा, केंद्रित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जब यह मेग्नेटिक फील्ड दिमाग में प्रवेश करता है, तो यह न्यूरोन्स (मस्तिष्क की कोशिकाओं) में छोटे विद्युत प्रवाह उत्पन्न



करती है। मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ. जेपी अग्रवाल ने बताया कि मानसिक बीमारियों में अक्सर मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरपेनेफिन का संतुलन बिगड़ जाता है। मेग्नेटिक सिस्टम में क्राइल से चुंबकीय किरणें निकलती हैं, जो इस असंतुलित हिस्से को संतुलित कर देती हैं। इस तकनीक की सफलता दर 80 से 90 प्रतिशत है। खासकर उन 50 प्रतिशत मरीजों के लिए जिन पर दवाएं असर नहीं करती हैं।3

जबलपुर में बी.टेक छात्र ने किया सुसाइड

सुसाइड नोट में लिखा- कुछ नहीं कर पा रहा हूं; परिजन बोले- बेटे का दांत टूटा, जबरदस्ती हुई

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक फर्स्ट ईयर के छात्र ने फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र का नाम प्रियांशु त्रिपाठी है, जो मैहर जिले का रहने वाला था। जबलपुर में वह शास्त्री नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

शनिवार देर रात जब मकान मालिक ने देखा कि काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला है, तो झांककर देखा तो प्रियांशु फंदे में लटकता हुआ था। सूचना पर पहुंची तिलवारा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सुसाइड नोट में लिखा- कुछ नहीं कर पा रहा- प्रियांशु के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि वह अपने माता-पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि पुलिस नोट की अन्य बातों की भी जांच कर रही है। छात्र के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से वह काफी परेशान रहने लगा था। उसे कुछ विषयों में बैक आई थी और उसने लोगों से मिलना-जुलना भी कम कर दिया था।

परिजन बोले- बेटे के साथ जबरदस्ती हुई, उसका दांत टूटा था

रविवार सुबह छात्र के परिजन मैहर से जबलपुर पहुंचे। उन्होंने छात्र की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार, प्रियांशु का शव दो गमछों से बने फंदे पर मात्र ढाई फीट ऊंचाई पर लटका था, जबकि उसके पैर जमीन से छू रहे थे। इसके अलावा मृतक का एक दांत टूटा हुआ था, जिससे जबरदस्ती या संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने छात्र के मोबाइल को साइबर जांच और सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की मांग की है। छात्र के दोस्तों के मुताबिक, 4 जून को आए रिजल्ट के बाद से ही वह तनाव में था और मिलना-जुलना भी कम कर दिया था।

पुलिस कर रही जांच

तिलवारा थाना एएसआई पी.एल. बंसल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साइबर एनालिसिस और सुसाइड नोट की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधर, छात्र का अंतिम संस्कार उसके गृह ग्राम करौंदी में किया जाएगा।

समर कैंप में बच्चों ने सीखे जीवन के मूल मंत्र

ब्रह्माकुमारीज़ सेवा केंद्रों पर हुआ आत्मविकास व संस्कार आधारित शिविर

विभिन्न स्कूलों व डांस स्टूडियोज़ में भी बच्चों को दी जा रही है आध्यात्मिक शिक्षा

भोपाल। गर्मियों की छुट्टियों को सिर्फ मौज-मस्ती तक सीमित न रखते हुए, ब्रह्माकुमारीज़ संस्था द्वारा बच्चों के लिए संस्कार व आत्मविकास पर आधारित समर कैम्प का आयोजन किया गया। एर्जांटिका सेवा केंद्र, विजय नगर सेवा केंद्र और ग्रीन एकड़ सेवा केंद्र पर आयोजित इन विशेष शिविरों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। शिविर में फन गेम्स, ड्राइंग, नृत्य, संगीत, कहानियाँ, समूह चर्चा, योग व राजयोग मेडिटेशन जैसे बहुआयामी सत्र आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बच्चों में एकाग्रता, आत्म-विश्वास, सकारात्मक



सोच और नैतिकता जैसे मूल्यों का विकास करना रहा। ‘मैं कौन हूँ’ से लेकर ‘सच्ची खुशी क्या है’ तक के विषयों पर संवाद ब्रह्माकुमारीज़ की वरिष्ठ बहनों और प्रशिक्षित शिक्षकों ने बच्चों से आत्म-चिंतन पर आधारित प्रश्नों जैसे मैं कौन

हूँ?, मेरे संस्कार कैसे बनते हैं? और शांति कहाँ मिलती है? जैसे विषयों पर संवाद कराए। बच्चों ने इन प्रश्नों को जीवनशैली से समझा और अपनी सहजशैली में उत्तरने की प्रेरणा ली। ध्यान (राजयोग मेडिटेशन) के सरल अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को

अपने विचारों की शक्ति को पहचानने और मानसिक शुद्धता की ओर अग्रसर होने का प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूलों और निजी संस्थानों में भी पहुंच रही ब्रह्माकुमारीज़ की सेवा

सिर्फ सेवा केंद्रों तक सीमित न रहते हुए, ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों, डांस स्टूडियोज़ एवं अन्य निजी समर कैम्प में भी विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, तनाव प्रबंधन, मन

की एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर रोचक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन संस्थानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह आज की पीढ़ी को तकनीकी दुनिया के तनाव से दूर ले जाकर एक संतुलित व

मूल्यनिष्ठ जीवन की ओर प्रेरित करने का श्रेष्ठ माध्यम है।

समापन पर प्रमाणपत्र व प्रस्तुतियाँ

शिविर के अंतिम दिन सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। बच्चों ने नृत्य, अभिनय, गीत और भाषणों के माध्यम से शिविर में सीखी बातों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कई अभिभावक इस दृश्य से भावुक हो उठे और संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे ‘संस्कारों की पाठशाला’ बताया।

संस्था का संदेश

ब्रह्माकुमारीज़ का यह प्रयास एक संदेश देता है कि यदि प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मिक शक्ति, नैतिक मूल्यों और शांति की सही दिशा मिले, तो वे एक संतुलित, सफल और मूल्यवान जीवन जी सकते हैं।

मध्यप्रदेश में 41 डॉक्टरों और अधिकारियों के तबादले

भोपाल के नए सीएमएचओ बने डॉ. मनीष शर्मा, बोले- पहली प्राथमिकता कोरोना को फैलने से रोकना

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) सहित कुल 41 चिकित्सकों, विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये तबादले सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति वर्ष 2025 के तहत किए गए हैं। इन्हें प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा शनिवार देर रात आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार, भोपाल का नया सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा को बनाया गया है। वे अब तक ग्वालियर में प्रभारी उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने कहा कि भोपाल के सीएमएचओ का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 को फैलने से रोकने की दिशा में काम करना होगी।

वहीं, भोपाल के वर्तमान सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी को वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन 41 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

- डॉ. राजेश कुमार अट्टया -सीएमएचओ, दमोह
- डॉ. राज सिंह ठाकुर -सीएमएचओ, कटनी
- डॉ. भरत कुमार खटीक - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी
- डॉ. राजेश प्रसाद तिवारी - प्रभारी, सीएमएचओ, पन्ना
- डॉ. मनोज कुमार हुमाडे - प्रभारी, सीएमएचओ, बैतूल
- डॉ. दिनेश खत्री, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, राजगढ़
- डॉ. हरिनारायण मांडे - प्रभारी, सीएमएचओ, रायसेन
- डॉ. बी. के. वर्मा - प्रभारी, सीएमएचओ, दतिया
- डॉ. दर्पण टोके - प्रभारी, सिविल सर्जन, बुरहानपुर
- डॉ. प्रदीप मोजेश - मुख्य खंडचिकित्सा अधिकारी, बुरहानपुर
- डॉ. वी. एस. चंदेल - प्रभारी, सीएमएचओ, उमरिया
- डॉ. शोभाराम रोशन - संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, सागर
- डॉ. धरित्री जे. मोहंती -सीएमएचओ, मंडला
- डॉ. पवन जैन - प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
- डॉ. एम. के. जोशी - संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, उज्जैन
- डॉ. जितेन्द्र राजपूत - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन
- डॉ. राजेश सिसोदिया - जिला चिकित्सालय, हरदा
- डॉ. किरण वाड्डिया - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. भूपे सिंह सैत्या - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, ग्वालियर
- डॉ. पवन शर्मा - शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, ग्वालियर
- डॉ. नीरज कुमार - शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, भिंड
- डॉ. अलका त्रिवेदी - प्रभारी, सीएमएचओ, अशोकनगर
- डॉ. के. सी. सरोत - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. माधव हसानी - प्रभारी, सीएमएचओ, इंदौर
- डॉ. राघेन्द्र कुमार खाड्योत - प्रभारी, सीएमएचओ, नीमच
- डॉ. रामहित कुमार - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा
- डॉ. मनीष शर्मा -सीएमएचओ, भोपाल
- डॉ. प्रभाकर तिवारी - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. दिनेश देहलवार - प्रभारी, सीएमएचओ, मालवा
- डॉ. राजेश गुप्ता - जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी, बड़वानी
- डॉ. मनोज कौरव - डीएचओ, ग्वालियर
- डॉ. नरसिंह गेहलोत - सीएमएचओ, नर्मदापुरम
- डॉ. सनेराम परस्ते - प्रभारी, सिविल सर्जन, अनूपपुर
- डॉ. अनिल झामनानी - प्रभारी, सीएमएचओ, निवाड़ी
- डॉ. रामकुमार गुप्ता - सीएमएचओ, ग्वालियर
- डॉ. प्रदीप कुमार जैन - शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, ग्वालियर
- डॉ. यशपाल सिंह - प्रभारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अश्रीक्षक, रायसेन
- डॉ. मुकेश जैन - शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, दमोह
- डॉ. एस. के. त्रिपाठी - प्रभारी, सीएमएचओ, पन्ना
- डॉ. राजेश परिहार - जिला परिवार कल्याण अधिकारी, बैतूल
- डॉ. सुशीला यादव - चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सागर

सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु की सगाई

खरगोन के बड़े किसान की बेटी डॉक्टर इशिता बनेंगी यादव परिवार की बहू



से पुत्र चिरंजीवी डॉ. अभिमन्यु यादव की सगाई, खरगोन के दिनेश यादव जी की सुपुत्री डॉ. इशिता यादव के साथ संपन्न हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत कई गणमान्य नेता शामिल थे।

पारंपरिक रीति से रिंग सेरेमनी, दोनों हैं डॉक्टर

सीएम हाउस में आयोजित सगाई समारोह में दोनों ने पारंपरिक पूजन के बाद एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। डॉ. अभिमन्यु यादव एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज भोपाल से मास्टर्स इन सर्जरी कर रहे हैं, वे सेंकेड इंयर में हैं। वहीं डॉ. इशिता एमबीबीएस कर रही हैं।

एमपी में 10 जून के बाद मानसून की एंट्री

8 जिलों में बारिश का अलर्ट; 9-10 जून को ग्वालियर-चंबल में लू चलेगी



भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होगी। इससे पहले प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज-चमक के साथ लू भी चलेगी। दक्षिणी हिस्से के 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है, जबकि 9 और 10 जून को ग्वालियर-चंबल में हीट वेव यानी, लू भी चल सकती है। इससे पहले शनिवार को इंदौर, नर्मदापुरम-बड़वानी में बारिश हुई। वहीं, 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 10 दिन से मानसून महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। इस वजह से एमपी में इसकी एंट्री लेट हो

रही है। अगले 3 से 4 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना कम ही है।

इन जिलों में आज मौसम बदला रहेगा

बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाण्डुरा और सिवनी में आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट है। वहीं, सोमवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना में लू का अलर्ट है। सिवनी, छिंदवाड़ा, पाण्डुरा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में गरज-चमक और बारिश वाला मौसम रह सकता है। इंदौर,

नर्मदापुरम, बड़वानी जिले में बारिश, 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार प्रदेश में शनिवार को मौसम के दो रंग देखने को मिले। इंदौर, नर्मदापुरम और बड़वानी के संंधवा में हल्की बारिश हुई। वहीं, ग्वालियर समेत 13 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, खजुराहो और गुना में पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, ग्वालियर, नैगांव, शाजापुर, सतना, टीकमगढ़ और शिवपुरी में 41 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। उज्जैन, सीधी, रीवा, सागर और रतलाम में तापमान 40.2 से 40.8 डिग्री तक रहा।

चलती ट्रेन से फिसला युवक, आरपीएफ जवान ने बचाया

भोपाल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा; प्लेटफार्म-कोच के बीच में फंस रहा था युवक

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन पर चढ़ते समय एक युवक का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। वह प्लेटफार्म और कोच के बीच में फंसने लगा। तभी आरपीएफ जवान ने दौड़ लगाई और खींचकर युवक को बचा लिया।

मामला शनिवार शाम का है, जो रविवार को सामने आया है। जानकारी के अनुसार, शाम को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म-1 से खाना हो रही

थी। इसी दौरान भोपाल के गांधीनगर निवासी अमरपाल सिंह प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अपने परिजनों को ट्रेन में बैठाने आए थे। अधिक सामान चढ़ाने के लिए कोच में गए थे। ट्रेन के चलने के बाद जब उन्होंने नीचे उतरने का प्रयास किया, तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर कोच और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े।

आरक्षक ने तुरंत खींचा- मौके पर मौजूद आरपीएफ आरक्षक कृष्ण कुमार ने हादसा होते देख दौड़ लगाई और युवक को खींचकर

बाहर निकाला। जिससे उसकी जान बच गई। युवक को केवल मामूली खरोंचें आईं। जिनका उपचार स्टेशन पर स्थित डिस्पेंसरी में किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि आरक्षक की सतर्कता और त्वरित निर्णय ने एक संभावित गंभीर हादसे को टाल दिया। उन्होंने यात्रियों से यह भी अपील की कि वे चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें और केवल गाड़ी के पूर्णतः रुकने पर ही चढ़ें या उतरें।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार की सुबह मुख्यमंत्री निवास पर गायों को दुलार किया और उन्हें रोटी खिलाई।

3 साल का बच्चा सीकर में किडनैप

मां और दादी के साथ खाटू श्याम दर्शन के लिए गया था, स्टेशन पर किडनैपर ने की दोस्ती

भोपाल (नप्र)। भोपाल से राजस्थान सीकर गए एक 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। बच्चा अपनी दादी और मां के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया। जैसे ही जयपुर स्टेशन पर पहुंचे, एक युवक उनसे मिला और कहा कि वह भी खाटू श्याम जा रहा है। इसके बाद वह उनके साथ चल दिया।



खाटू प्रयागजी मंदिर पहुंचने पर युवक ने भीड़ का बहाना बनाया और बच्चे को अपने पास रखकर मां-दादी को दर्शन के लिए भेज दिया। जब दोनों महिलाएं दर्शन करके लौटीं तो न तो बच्चा मिला और न ही वह युवक। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों में भी तलाश अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है।

एकादशी पर दर्शन करने पहुंचे थे

भोपाल से एकादशी पर दर्शन के लिए आए परिवार के साथ बड़ी वारदात हो गई। मां ने बताया कि 6 जून को वह 3 साल के बेटे रक्षम और सास आशा के साथ ट्रेन से जयपुर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर एक युवक से मुलाकात हुई, जो खाटू जाने की बात कहकर उनके साथ हो लिया।

खाटू पहुंचने पर युवक ने मासिक मेले की भीड़ का बहाना बनाया। मां-दादी को दर्शन के लिए भेज दिया और बच्चे को अपने पास रख लिया। जब दोनों महिलाएं लौटीं तो बच्चा और युवक गायब थे।

थाने के आसपास भी घूमा, फिर गायब हो गया

पुलिस जांच में सामने आया कि किडनैपर बच्चे को एक दुकान पर ले गया, जहां उसे फस्टी पिलाई। वह पुलिस थाने के आसपास भी घूमा, फिर कहीं गायब हो गया। 7 जून की शाम को मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देश पर कई टीमें संचर्च कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आसपास के इलाकों में तलाश जारी है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज पुलिस मुख्यालय के पुराने कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था श्री अंशुमान सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी तथा रेंडियो में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 6,52,057 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। प्रक्रिया के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार 55,220 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन शाखा, मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य आयोजित की थी। संपूर्ण प्रक्रिया के उपरांत कुल 6423 अभ्यर्थी (5090 पुरुष एवं 1333 महिला) का चयन किया गया था। द्वितीय चरण के शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान नवम्बर 2024 में परीक्षा केन्द्र मुरैना में 05 अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु भेजा गया, जिन्हें संदिग्ध पाते हुए, परीक्षा में शामिल न कर उक्त उम्मीदवारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही



की गई थी।

इस अनुभव के आधार पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अंतिम परिणाम जारी होने के उपरांत सभी सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं नैतिक प्रक्रिया के दौरान उनकी आवंटित इकाईयों से बायोमेट्रिक एवं आधार बिस्ट्री की जांच पुनः कराये जाने हेतु निर्दिष्ट 21-04-2025 को निर्देश जारी किये गये। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में कुछ जिलों में संदिग्ध रूप से भिन्नता पाये जाने पर

बारीकी से जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के पूर्व अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक ठीक बाद उनके द्वारा पुनः आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया। ऐसे अभ्यर्थियों पर संदेह के आधार पर इनकी जांच कराई गई, जिसमें इनके हस्ताक्षर नमूना, हस्तलिपि, फिंगर प्रिंट लिये गये। साथ ही परीक्षा के दौरान इनके द्वारा दिये गये फिंगर प्रिंट, हस्तलिपि, के नमूने को प्राप्त कर उनकी जांच कराई गई। अभ्यर्थियों की वास्तविक लोकेशन के संबंध में तकनीकी रूप से भी जांच कराई गई, जिसमें भिन्नता पाये जाने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। अभी तक कुल 21 प्रकरण 22 अभ्यर्थियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किये जा चुके हैं, जिसमें मुरैना में 07, शिवपुरी-06, रयपुर-02 तथा इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़ तथा शहडोल में 01-01 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आये हैं कि कुछ आधार कार्ड बेण्डों द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों के आधार कार्ड को बिना पूरी तरह जांच किये संशोधन के लिए अपने सिस्टम में अपलोड किया गया था।

परीक्षा पास करने वाले हर आरक्षक की अंकसूचियों की होगी जांच

पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जीवाड़ा कर पास हुए नवआरक्षकों के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ग्वालियर-चंबल में अब तक 22 आरक्षक पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी जगह किसी साल्वर को बैठकर परीक्षा पास की है। जांच में जुटे अफसरों को अब संदेह है कि कई आरक्षकों को बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट भी फर्जी हो सकती है, इसलिए नवआरक्षकों की अंकसूचियों की भी जांच करवाई जाएगी।

धोखाधड़ी व परीक्षा अधिनियम की धाराओं में एफआईआर

गौरतलब है, कि आरक्षक भर्ती के बाद हर जिले को नवआरक्षकों का कोटा दिया गया है। मुरैना जिला पुलिस को 38 और 5वीं बटालियन को 106 आरक्षकों का कोटा मिला है। इनमें से बटालियन में अब तक पांच ऐसे आरक्षक पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो व बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट बदलवाकर साल्वर के जरिए भर्ती परीक्षा पास की। जिला पुलिस भी ऐसे दो नवआरक्षक पकड़ चुकी है। इन सातों पर धोखाधड़ी व परीक्षा अधिनियम की धाराओं में एफआईआर हो चुकी है।